Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

24 & 25 अगस्त 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. केंद्र ने अगली पीढ़ी के सुधारों और विकसित भारत विजन को आगे बढ़ाने के लिए राजीव गौबा के नेतृत्व में पैनल गठित किए।

अगस्त 2025 के अंत में, भारत सरकार ने नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में दो उच्चस्तरीय सुधार पैनल स्थापित किए, ताकि 2047 तक के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप अगली पीढ़ी के नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाया जा सके।

- **भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान शासन, कराधान और सार्वजनिक सेवा वितरण में अगली पीढ़ी के सुधारों का प्रस्ताव और कार्यान्वयन करने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की, जिससे इन औपचारिक पैनलों का मार्ग प्रशस्त हुआ।**

- **नवगठित पैनल में वरिष्ठ सचिव, टेक्नोक्रेट और अर्थशास्त्री शामिल हैं, और इन्हें संस्थागत और आर्थिक सुधारों को पुनर्जीवित करने का दायित्व सौंपा गया है - जिसमें गैर-वित्तीय क्षेत्रों में नियामक सुधार और 21वीं सदी के वैश्विक मानकों के साथ कानूनों, नीतियों और प्रथाओं का रणनीतिक संरेखण शामिल है।**

Key Points:-

(i) पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, जो अब मार्च 2025 से पूर्णकालिक नीति आयोग के सदस्य के रूप में राज्य मंत्री (MoS) के पद पर हैं, नीति सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए अपने व्यापक प्रशासनिक अनुभव का लाभ उठाते हुए दोनों पैनलों की अध्यक्षता करेंगे।

(ii) ये सुधार भारत को विकसित भारत 2047 के पथ पर अग्रसर करने के लिए अभिन्न अंग हैं, जो एक महत्वाकांक्षी रोडमैप है जो अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक विकसित, समावेशी और नवाचार-संचालित राष्ट्र की परिकल्पना करता है। इस दृष्टिकोण में शासन में परिवर्तन, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और विविध क्षेत्रों में नागरिकों को सशक्त बनाना शामिल है।

(iii) इन समितियों को समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने, बहु-क्षेत्रीय समन्वय स्थापित करने और व्यवस्थागत बदलावों की सिफ़ारिश करने का काम सौंपा गया है, जो भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र के निर्माण के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इनके परिणामों से विकसित भारत के बैनर तले भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को साकार करने के लिए आवश्यक नीतिगत रोडमैप तैयार होने की उम्मीद है।

2. केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बन गया।

अगस्त 2025 में, केरल ने भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बनकर इतिहास रच दिया—यह उपलब्धि उसने अपनी डिजी केरल पहल के ज़रिए हासिल की। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस उपलब्धि की घोषणा की, जिसके तहत राज्य भर में 21.87 लाख लोगों को ज़रूरी डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण दिया गया।

• केरल की यह उपलब्धि उच्च साक्षरता की उसकी विरासत पर आधारित है, जहां पूर्ण पारंपरिक साक्षरता पहली बार 1991 में प्राप्त की गई थी। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसी भावना को दोहराते हुए इस उपलब्धि को प्रगति और सशक्तिकरण में एक "बड़ी छलांग" बताया, जो समावेशी, ज्ञान-संचालित विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

• 2023 में शुरू किए गए DG केरल कार्यक्रम ने सभी आयु वर्गों में डिजिटल साक्षरता का विस्तार किया और 83 लाख से ज़्यादा घरों में सर्वेक्षण किया। इसके बाद, वरिष्ठ नागरिकों सहित 21.87 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे डिजिटल कौशल में महारत हासिल करने में 99.98% की उल्लेखनीय सफलता दर हासिल हुई।

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), नेहरू युवा केंद्र और कुदुम्बश्री के सदस्यों सहित 2.57 लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने सामुदायिक पहुंच का नेतृत्व किया, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने और हाशिए पर रहने वाली आबादी तक डिजिटल पहुंच बनाने में मदद मिली।

Key Points:-

(i) डिजिटल यात्रा तिरुवनंतपुरम जिले के एक गांव पुल्लमपारा से शुरू हुई, जो 2022 में भारत की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई। यह सफलता एक अनुकरणीय मॉडल बन गई जिसने राज्यव्यापी डिजी केरल रोलआउट को बढ़ावा दिया।

(ii) इस अभियान का प्रभाव आँकड़ों से कहीं आगे निकल गया, अब्दुल्ला मौलवी (105) और करुणाकरण (104) जैसे शतायु लोगों ने परिवार को वीडियो कॉल करने, यूट्यूब, व्हाट्सएप का उपयोग करने और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए स्मार्टफोन का सहारा लिया। उनकी कहानियाँ डिजिटल समानता के प्रति केरल के समावेशी दृष्टिकोण को उजागर करती हैं।

3. असम सरकार ने एसएसए के तहत युवा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नेल्को लिमिटेड के साथ 600 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी।

सत्यमेव जयते
GOVERNMENT OF ASSAM

22 अगस्त 2025 को, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम सरकार ने समग्र शिक्षा योजना (SSA) ढांचे के तहत राज्य भर में कौशल शिक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए नेल्को लिमिटेड (टाटा पावर की सहायक कंपनी) के साथ 600 करोड़ रुपये की साझेदारी को मंजूरी दी।

• इस परियोजना का उद्देश्य एक मजबूत हब-एंड-स्पोक मॉडल बनाकर असम के युवाओं के लिए कौशल-आधारित शिक्षा को मजबूत करना है, जो स्कूलों को कई क्षेत्रों में उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों से जोड़ता है।

• इस सहयोग के तहत, नेल्को लिमिटेड उपग्रह संचार सुविधाएं प्रदान करेगा, जबकि असम सरकार SSA ढांचे के तहत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यान्वयन की देखरेख करेगी।

• वित्तपोषण पैटर्न में नेल्को लिमिटेड के माध्यम से टाटा समूह द्वारा 75% निवेश शामिल है, जबकि शेष 25% का योगदान असम सरकार द्वारा किया जाएगा, जिससे यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल बन जाएगा।

Key Points:-

(i) पहले कार्यान्वयन चरण में, 10 हब और 70 स्पोक स्थापित किए जाएँगे। प्रत्येक हब 10 भविष्योन्मुखी ट्रेडों या क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें प्रत्येक हब में दो प्रशिक्षक होंगे, जबकि स्पोक दो-दो ट्रेडों में छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे।

(ii) इस बड़ी योजना का लक्ष्य असम में 50 हब और 500 स्पोक की स्थापना करना है, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा में बदलाव लाना तथा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करना है।

(iii) यह परियोजना युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष समर्थन करती है, साथ ही एकीकृत स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समग्र शिक्षा योजना (SSA) ढांचे के साथ संरेखित होती है।

4. प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

22 अगस्त 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ₹5,200 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें तीन प्रमुख मेट्रो खंड और एक छह-लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे शामिल हैं, जिनका उद्देश्य मेट्रो, रेल और सड़क नेटवर्क में शहरी गतिशीलता और अंतर-संचालन को बढ़ाना है।

• प्रधानमंत्री मोदी ने तीन नए कोलकाता मेट्रो कॉरिडोर को हरी झंडी दिखाई, जिससे नेटवर्क में लगभग 14 किलोमीटर की वृद्धि हुई और शहर का ट्रांजिट ग्रिड 74 किलोमीटर तक विस्तारित हुआ। इनमें सियालदह-एस्प्लेनेड (ग्रीन लाइन), नोआपारा-जय हिंद विमानबंदर (येलो लाइन), और हेमंत मुखोपाध्याय-बेलेघाटा (ऑरेंज लाइन) खंड शामिल हैं—जो हवाई अड्डे, हावड़ा और IT जिले जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे।

• प्रमुख विस्तारों में से एक नोआपाड़ा से जय हिंद (हवाई अड्डा) स्टेशन तक येलो लाइन का विस्तार है—जो कोलकाता का पहला मेट्रो-हवाई अड्डा संपर्क मार्ग है। उद्घाटन के बाद से चालू यह 7 किलोमीटर लंबा मार्ग शहर और हवाई अड्डे के बीच यात्रा के समय को उल्लेखनीय रूप से कम करता है, जिससे यात्रियों को हवाई अड्डे तक निर्बाध पहुँच मिलती है।

Key Points:-

(i) ईस्ट-वेस्ट मेट्रो (ग्रीन लाइन) पर सियालदाह-

एस्प्लेनेड सेक्शन आखिरकार पूरी तरह से चालू हो गया, जिससे हुगली नदी के रास्ते सेक्टर-V से हावड़ा मैदान तक 16.6 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट पूरा हो गया। यह उपलब्धि पहचान-परिभाषित बुनियादी ढाँचे के निर्माण के 16 साल के प्रयास की परिणति है।

(ii) रेल परियोजनाओं के अलावा, प्रधानमंत्री ने 7.2 किलोमीटर लंबे, छह लेन वाले एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। ₹1,200 करोड़ से अधिक की लागत वाला यह एलिवेटेड रोड कॉरिडोर हावड़ा, उसके बाहरी इलाकों और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार लाएगा, जिससे भीड़भाड़ कम होगी और आवागमन की दक्षता बढ़ेगी।

(iii) प्रधानमंत्री मोदी ने शहरी विकास के लिए 21वीं सदी के परिवहन बुनियादी ढाँचे—मेट्रो, रेल और सड़कों को जोड़ने—की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने भारत में मेट्रो के तेज़ विस्तार—जो 2014 में 250 किलोमीटर से बढ़कर 2025 तक 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा—पर भी प्रकाश डाला। समावेशी सार्वजनिक परिवहन और अपशिष्ट से धन और हरित गतिशीलता जैसी पहलों को आधुनिक भारत की प्रगति के प्रतीक के रूप में रेखांकित किया गया।

5. MoTA ने 'आदि कर्मयोगी अभियान' लॉन्च किया - जो दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी जमीनी स्तर का नेतृत्व कार्यक्रम है।

अगस्त 2025 में, जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने दुनिया के सबसे बड़े आदिवासी जमीनी स्तर के नेतृत्व कार्यक्रम, आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप, आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना, उत्तरदायी शासन को मज़बूत करना और पूरे भारत में स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देना है।

• आदि कर्मयोगी अभियान को 20 लाख आदिवासी परिवर्तन नेताओं को प्रशिक्षित और पोषित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेतृत्व आंदोलन के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह व्यापक कार्यक्रम भारत के 550 जिलों और सभी 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) को कवर करते हुए 1 लाख आदिवासी गाँवों तक फैला होगा, जिससे व्यापक भागीदारी और समावेशिता सुनिश्चित होगी।

• यह कार्यक्रम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA), प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN), और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (NSCEM) जैसी प्रमुख पहलों की नींव पर आधारित है। इन योजनाओं ने पहले ही जनजातीय कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अब इन्हें नए नेतृत्व ढांचे के अंतर्गत एकीकृत किया जाएगा।

• इस अभियान का मुख्य ज़ोर सेवा, संकल्प और समर्पण के मूल्यों पर है, जो "सबका साथ, सबका

विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास" के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है। इस मूल्य-आधारित दृष्टिकोण का उद्देश्य देश के जनजातीय क्षेत्रों में सतत और समावेशी विकास लाना है।

Key Points:-

(i) आदि कर्मयोगी अभियान, जनजातीय गौरव वर्ष का भी एक प्रमुख अंग है, जो राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों के योगदान का स्मरण कराता है। जमीनी स्तर पर आदिवासी नेतृत्व को एकीकृत करके, सरकार गाँव और समुदाय के स्तर पर उत्तरदायी शासन और मज़बूत लोकतांत्रिक भागीदारी के मार्ग प्रशस्त करना चाहती है।

(ii) कार्यक्रम के उद्देश्यों में राज्यों, जिलों, ब्लॉकों और गांवों में बहु-विभागीय शासन प्रयोगशाला कार्यशालाएं/प्रक्रिया प्रयोगशालाएं आयोजित करना शामिल है।

(iii) ये राज्य, जिला और ब्लॉक मास्टर प्रशिक्षकों जैसे क्षमता निर्माताओं को उत्तरदायी शासन मॉडल लागू करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, जिससे जनजातीय युवाओं और नेताओं को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जा सकेगा।

INTERNATIONAL

1. ट्रम्प ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत तथा दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया।

22-23 अगस्त 2025 को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने करीबी सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित करने की घोषणा की, साथ ही उन्हें दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत का पद भी दिया, जो उनके क्षेत्रीय राजनयिक जनादेश में रणनीतिक विस्तार का संकेत था।

- **राष्ट्रपति ट्रंप ने बढ़ते व्यापार गतिरोध के दौरान ट्रुथ सोशल के ज़रिए इस नामांकन की घोषणा की— 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने की योजना के बीच। राजदूत और दूत की भूमिकाएँ भारत और पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में अमेरिका के ठोस कदम को दर्शाती हैं।**

- **सर्जियो गोर की दोहरी ज़िम्मेदारी पहली बार है जब भारत में किसी अमेरिकी राजदूत को व्यापक दक्षिण और मध्य एशियाई क्षेत्र के लिए विशेष दूत भी नियुक्त किया गया है। इससे उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान जैसे महत्वपूर्ण पड़ोसियों के साथ अमेरिकी संबंधों की देखरेख का दायित्व मिलेगा।**

Key Points:-

(i) ट्रंप के लंबे समय से सलाहकार रहे सर्जियो गोर वर्तमान में व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति कार्मिक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। सुरक्षा मंज़ूरी में देरी और

कथित पिछले विवादों—खासकर एलन मस्क से जुड़े—की जाँच के बावजूद, राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रमुख पदों पर नियुक्ति में उनकी निष्ठा और प्रभावशीलता की सराहना की।

(ii) अमेरिकी सीनेट द्वारा पुष्टि होने तक, गोर व्हाइट हाउस में अपनी मौजूदा भूमिका निभाते रहेंगे। राजदूत की भूमिका के लिए सीनेट की पुष्टि आवश्यक है, जबकि विशेष दूत के पद के लिए नहीं—जो दोनों भूमिकाओं में एक निर्बाध निरंतरता को दर्शाता है।

(iii) पर्यवेक्षक गोर के नामांकन को जटिल वैश्विक गतिशीलता के बीच भारत पर बढ़ते अमेरिकी ध्यान का प्रतिबिंब मानते हैं। उनके विस्तारित कार्यक्षेत्र से दक्षिण एशिया में गहन राजनीतिक और रणनीतिक एकीकरण की दिशा में एक कदम का संकेत मिलता है—जो कूटनीति, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग जैसी पहलों को संभावित रूप से नया रूप दे सकता है।

2. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए रूस की 3 दिवसीय यात्रा (19-21 अगस्त, 2025) का समापन किया।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने प्रथम उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के निमंत्रण पर 19 से 21 अगस्त 2025 तक मास्को की एक उच्च-स्तरीय यात्रा की। उन्होंने 26वें भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (IRIGC-TEC) की सह-अध्यक्षता की, व्यापारिक और रणनीतिक नेताओं के साथ बातचीत की और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय संवादों को मज़बूत किया।

• 20 अगस्त को, डॉ. जयशंकर ने श्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (IRIGC-TEC) के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता की, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला, निवेश और द्विपक्षीय व्यापार महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज के लिए भारत-रूस व्यापार मंच को भी संबोधित किया।

• पूरे दौरे के दौरान, विदेश मंत्री ने भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापार घाटे से निपटने के लिए तत्काल उपाय करने का आह्वान किया, जो मुख्यतः ऊर्जा आयात में वृद्धि के कारण बढ़कर लगभग 58.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। उन्होंने संतुलित आर्थिक संबंधों की वकालत की।

• डॉ. जयशंकर ने क्रेमलिन में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और बाद में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं। चर्चा में क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रम और सतत सहयोग सहित व्यापक रणनीतिक विषयों पर चर्चा हुई।

Key Points:-

(i) इस यात्रा के दौरान, रूसी राजनयिकों ने भारत को तेल की आपूर्ति जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों से निपटने के लिए एक "विशेष प्रणाली" मौजूद है, और बाहरी दबावों के बीच भारत-रूस ऊर्जा साझेदारी की विश्वसनीयता पर ज़ोर दिया।

(ii) विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि डॉ. जयशंकर ने यूक्रेन, पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की तथा भारत-रूस "विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त

रणनीतिक साझेदारी" को मजबूत करने के प्रयासों की भी समीक्षा की।

(iii) यह यात्रा अमेरिका द्वारा रूस से तेल आयात के जवाब में भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाने की कूटनीतिक कार्रवाई के साथ हुई। इस पृष्ठभूमि में, मास्को के साथ भारत के संबंधों ने भू-राजनीतिक संतुलन बनाए रखने और अपनी सामरिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखने के उसके संकल्प को रेखांकित किया।

BANKING & FINANCE

1. PFC ने RDSS परियोजनाओं के समर्थन के लिए जर्मनी की KfW के साथ 150 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

अगस्त 2025 में, विद्युत मंत्रालय (MoP) के अंतर्गत एक 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) ने जर्मनी की Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) के साथ 150 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस ऋण का उपयोग पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत भारत के विद्युत वितरण नेटवर्क को मज़बूत करने के लिए किया जाएगा।

• इस समझौते पर नई दिल्ली में PFC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) परमिंदर चोपड़ा और KfW के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) स्टीफन विंटेल्स ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास के आर्थिक मामलों के प्रभाग प्रमुख गॉटफ्रीड वॉन जेमिंगेन भी उपस्थित थे। यह ऊर्जा परिवर्तन और बिजली सुधारों के क्षेत्र में बढ़ते भारत-जर्मनी सहयोग को दर्शाता है।

• PFC द्वारा सुरक्षित ऋण विशेष रूप से भारत सरकार (GoI) की पुनरीक्षित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत पहचानी गई परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा, जिसे 2021 में 3,03,758 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था।

• RDSS का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) घाटे में कमी के माध्यम से भारत की बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।

Key Points:-

(i) यह साझेदारी भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल सरकार के प्रमुख RDSS कार्यक्रम को एक मज़बूत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, बल्कि भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को भी बढ़ाती है। जर्मनी भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा विकास और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के समर्थन में, एक प्रमुख भागीदार रहा है।

(ii) इस 150 मिलियन यूरो के ऋण से स्मार्ट मीटरों के कार्यान्वयन में तेज़ी आने, वितरण ढाँचे को मज़बूत करने और बिजली आपूर्ति में व्यवधान कम होने की उम्मीद है। यह अंततः पूरे भारत में किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ बिजली पहुँच सुनिश्चित करने के दीर्घकालिक लक्ष्य में योगदान देगा।

(iii) यह समझौता भारत के अग्रणी विद्युत क्षेत्र वित्तपोषक के रूप में PFC की भूमिका और उसकी बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को दर्शाता है। इस ऋण के साथ, पीएफसी घरेलू विद्युत सुधारों को समर्थन

देने के लिए वैश्विक वित्तीय संसाधन जुटाना जारी रखेगा, जो भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के तहत ऊर्जा परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

2. एलएंडटी फाइनेंस ने व्यक्तिगत ऋण की पेशकश करने के लिए गूगल पे के साथ साझेदारी की, जिससे डिजिटल क्रेडिट पहुंच बढ़ेगी।

अगस्त 2025 में, भारत की एक प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) L&T फाइनेंस ने वित्तीय समावेशन, सुविधा और ऋण पहुंच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से पात्र उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत ऋण उत्पाद प्रदान करने के लिए गूगल पे के साथ एक रणनीतिक गठबंधन किया।

- **L&T फाइनेंस और गूगल पे के बीच यह सहयोग NBFC की उत्पाद विविधीकरण रणनीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य डिजिटल टचपॉइंट्स के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण को सहज, त्वरित और सुलभ बनाना है। यह साझेदारी गूगल पे के व्यापक उपयोगकर्ता आधार और ऐप इंटरफ़ेस का लाभ उठाकर कुशलतापूर्वक ऋण प्रदान करती है।**

Key Points:-

(i) गूगल पे के साथ ऋण सेवाओं को एकीकृत करके, यह पहल भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी। पात्र उपयोगकर्ता बिना किसी भौतिक शाखा में जाए व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को एक परिचित ऐप इंटरफ़ेस का उपयोग करके ज़िम्मेदारी से वित्तीय ज़रूरतें पूरी करने का अधिकार मिलता है।

(ii) इस साझेदारी के माध्यम से, उधारकर्ताओं को तीव्र, डिजिटल-प्रथम अनुभव का लाभ मिलता है: पूर्व-स्वीकृत प्रस्तावों को सीधे ऐप में देखा जा सकता है, व्यक्तिगत जानकारी पहले से भरी हुई होती है, और कागजी कार्रवाई न्यूनतम होती है, जिससे सुविधा बढ़ती है और ऋण प्राप्ति में कठिनाई कम होती है।

(iii) यह सहयोग एक व्यापक बदलाव का संकेत देता है जहाँ NBFCs अपनी पहुँच बढ़ाने और अधिग्रहण लागत कम करने के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ा रहे हैं। L&T फाइनेंस और गूगल पे के बीच साझेदारी से, यह मॉडल वंचित क्षेत्रों में डिजिटल ऋण को बढ़ाने में उभरती हुई सहक्रियाओं को रेखांकित करता है।

3. JICA ने एशिया और अफ्रीका में SMEs को बढ़ावा देने के लिए आविष्कार कैपिटल के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सहायता कोष में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया।

JICA
Japan International Cooperation Agency

22 अगस्त, 2025 को, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) ने आविष्कार कैपिटल द्वारा प्रबंधित ग्लोबल सप्लाई चेन सपोर्ट फंड में 40 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश की घोषणा की, जिसका उद्देश्य एशिया और अफ्रीका में आपूर्ति श्रृंखलाओं में कार्यरत लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) को मजबूत करना है।

• JICA फंडिंग का उद्देश्य एशिया और अफ्रीका के उभरते बाजारों में आविष्कार कैपिटल के विस्तार के लिए मजबूत समर्थन प्रदान करना है, जिससे एसएमई को परिचालन बढ़ाने, नए बाजारों तक पहुंचने और वैश्विक आपूर्ति नेटवर्क में भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

• यह कदम निजी क्षेत्र के सहयोग के माध्यम से सतत विकास और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के JICA के व्यापक मिशन के अनुरूप है।

• यह फंड मुख्य रूप से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में लगे लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) पर केंद्रित होगा, जो वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। पूंजी और तकनीकी सहायता प्रदान करके, इस पहल का उद्देश्य लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) के बीच नवाचार को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से जिम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

Key Points:-

(i) इस निवेश का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक, पर्यावरणीय और प्रभाव-आधारित परिणाम उत्पन्न करने वाले लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) को वित्तीय सहायता प्रदान करके आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता का निर्माण करना है। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय न केवल आर्थिक रूप से विकसित हों, बल्कि समतामूलक विकास और जलवायु-अनुकूल व्यावसायिक प्रथाओं में भी योगदान दें।

(ii) यह आविष्कार कैपिटल द्वारा शुरू किया गया आठवां फंड है, जिसमें ग्लोबल सप्लाई चेन सपोर्ट फंड की स्थापना KfW (क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेरॉफबाउ - जर्मन डेवलपमेंट बैंक) के सहयोग से की गई है।

(iii) यह साझेदारी विकासशील क्षेत्रों में SMEs के लिए प्रभावी पूंजी जुटाने के लिए एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को दर्शाती है, जिससे एशिया और अफ्रीका में आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।

MOUs and Agreement

1. ओडिशा पर्यटन विभाग ने विरासत, साहसिक और बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IIT-M, NIWS गोवा और LBDFI के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

अगस्त 2025 में, ओडिशा के पर्यटन विभाग ने राज्य भर में विरासत संरक्षण, साहसिक पर्यटन और बौद्ध तीर्थयात्रा सर्किट को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख भारतीय संगठनों के साथ तीन समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञापन IIT मद्रास (IIT-M), राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (NIWS), गोवा और लाइट ऑफ बुद्धधर्म फाउंडेशन इंटरनेशनल (LBDFI) के साथ हस्ताक्षरित किए गए।

• IIT मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन, ऐतिहासिक स्मारकों के संरचनात्मक ऑडिट और संरक्षण के लिए उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों पर केंद्रित है। इसमें विस्तृत दस्तावेज़ीकरण, सामग्री परीक्षण, भू-तकनीकी जाँच और परियोजना रिपोर्ट तैयार करना शामिल है, जिससे ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण में वैज्ञानिक सटीकता सुनिश्चित होगी।

• IIT-M साझेदारी की एक अन्य प्रमुख विशेषता स्थायी पुनः उपयोग योजनाओं और परियोजना प्रबंधन के लिए परामर्श सहायता पर ज़ोर है। इन उपायों का उद्देश्य ओडिशा के ऐतिहासिक स्थलों का दीर्घकालिक संरक्षण करना है, जिसमें पारंपरिक विरासत को आधुनिक संरक्षण तकनीकों के साथ जोड़ा जाएगा।

• गोवा के राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (NIWS) के साथ समझौता ज्ञापन का उद्देश्य साहसिक और जल पर्यटन में सुरक्षा और मानकीकरण को बढ़ावा देना है। NIWS सुरक्षा प्रोटोकॉल पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा, मूल्यांकन करेगा और पर्यटन संचालकों एवं लाइफगार्डों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगा, जिससे ओडिशा के साहसिक पर्यटन क्षेत्र के पेशेवर मानकों में वृद्धि होगी।

Key Points:-

(i) ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग के सहयोग से लाइट ऑफ बुद्धधर्म फाउंडेशन इंटरनेशनल (LBDFI) के साथ सहयोग का उद्देश्य ओडिशा की समृद्ध बौद्ध विरासत को पुनर्जीवित करना है।

(ii) यह समझौता ज्ञापन धार्मिक पर्यटन के साथ विरासत संवर्धन को एकीकृत करते हुए बौद्ध तीर्थयात्रा सर्किट विकसित करने पर केंद्रित है, जिससे ओडिशा को आध्यात्मिक यात्रियों के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

(iii) इन तीन समझौता ज्ञापनों के माध्यम से, ओडिशा एक अग्रणी सांस्कृतिक और साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत करना चाहता है। उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान, उन्नत सुरक्षा उपायों और बौद्ध विरासत के पुनरुद्धार को मिलाकर, राज्य पर्यटन विकास को आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों के साथ जोड़ रहा है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. RBI ने इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में अपने कार्यकारी निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति (MPC) का पदेन सदस्य नियुक्त करने की घोषणा की। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की 618वीं बैठक के दौरान लिया गया।

• इंद्रनील भट्टाचार्य, राजीव रंजन का स्थान लेंगे, जिन्हें अब आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग (DEPR) का प्रमुख नियुक्त किया गया है। MPC की बैठक की अध्यक्षता RBI के 25वें गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की और इसमें आर्थिक स्थितियों और मौद्रिक नीति ढाँचों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।

• केंद्रीय निदेशक मंडल की 618वीं बैठक में वैश्विक और घरेलू आर्थिक विकास की समीक्षा की गई,

जिसमें भू-राजनीतिक तनावों और वित्तीय बाज़ार की अस्थिरता से उत्पन्न चुनौतियों पर विशेष ज़ोर दिया गया। बैठक में केंद्रीय कार्यालय विभागों, बोर्ड समितियों और लोकपाल योजना के कामकाज का भी मूल्यांकन किया गया, ताकि RBI के नीतिगत उद्देश्यों के साथ उनका तालमेल सुनिश्चित किया जा सके।

• बैठक में RBI के डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव, टी. रबी शंकर, स्वामीनाथन जे. और डॉ. पी. के. मोहंती प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सरकार का प्रतिनिधित्व वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव नागराज मुदलियार और आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की सचिव अनुराधा ठाकुर ने किया।

Key Points:-

(i) सतीश के. मराठे, रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी, आनंद गोपाल महिंद्रा (महिंद्रा समूह के अध्यक्ष), पंकज रमनभाई पटेल (ज़ाइडस लाइफसाइंसेज लिमिटेड के अध्यक्ष) और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया सहित प्रमुख बोर्ड सदस्यों ने भी भाग लिया। उनकी भागीदारी ने केंद्रीय बैंकिंग नीति और कॉर्पोरेट-आर्थिक दृष्टिकोण के बीच मज़बूत संबंध को उजागर किया।

(ii) इंद्रनील भट्टाचार्य को केंद्रीय बैंकिंग में 28 वर्षों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने अपने करियर का दो-तिहाई से अधिक समय मौद्रिक नीति विभाग (MPD) में बिताया है। उन्होंने RBI के MPD में सलाहकार के रूप में भी काम किया और 2009 से 2014 के बीच पाँच वर्षों तक कतर सेंट्रल बैंक (QCB), दोहा में आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त किया।

(iii) RBI अधिनियम, 1934 के तहत गठित MPC में छह सदस्य होते हैं—तीन RBI द्वारा नामित और तीन बाहरी विशेषज्ञ। यह बेंचमार्क ब्याज दरें निर्धारित करने, मौद्रिक नीति को आकार देने और समग्र वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है, जिससे भट्टाचार्य की नियुक्ति RBI की भविष्य की रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बन जाती है।

2. विलंबित चुनावों और कानूनी विवादों के बीच अजय सिंह लगातार तीसरी बार BFI अध्यक्ष चुने गए।

स्पाइसजेट के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) अजय सिंह को हाल ही में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (BFI) का अध्यक्ष चुना गया है। उनका पुनर्निर्वाचन BFI के नेतृत्व में निरंतरता को मज़बूत करता है और ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुआ है जब भारतीय मुक्केबाजी आगामी वैश्विक टूर्नामेंटों की तैयारी कर रही है।

• अजय सिंह का पुनर्निर्वाचन अगस्त 2025 में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की वार्षिक आम बैठक (AGM) के दौरान हुआ। ये चुनाव युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की देखरेख में हुए, जिसमें पारदर्शिता और भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

• यह सिंह का तीसरा कार्यकाल है, जब से उन्होंने 2016 में पहली बार पदभार संभाला था, उसके बाद 2020 में उनका फिर से चुनाव हुआ। उनके नेतृत्व में, BFI ने अपनी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति का विस्तार किया है, जिसमें भारत द्वारा 2018 में AIBA

(अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ) महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप और 2023 में IBA (अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ) पुरुष विश्व चैंपियनशिप बोली प्रक्रिया की मेजबानी शामिल है।

• इस पुनर्निर्वाचन को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सिंह ने भारत के मुक्केबाजी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने उच्च-प्रदर्शन केंद्रों के विकास में मदद की है, जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण में सुधार किया है और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के सहयोग से मुक्केबाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन दौरे शुरू किए हैं।

Key Points:-

(i) युवा मामले और खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के प्रतिनिधि, एजीएम में शामिल हुए।

(ii) BFI ने महिला मुक्केबाजी को मजबूत करने और ओलंपिक तैयारियों के अनुरूप एथलीटों के प्रदर्शन में सुधार के लिए उन्नत विश्लेषण और खेल विज्ञान पद्धतियों को लागू करने की योजना की भी घोषणा की।

(iii) अजय सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके अगले कार्यकाल का तत्काल ध्यान 2026 में जापान के नागोया में होने वाले एशियाई खेलों और 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक पर होगा। उन्होंने भारत के लिए और अधिक पदक जीतने और वैश्विक मुक्केबाजी महासंघों के साथ साझेदारी बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे भारत विश्व मुक्केबाजी में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित हो सके।

SPORTS

1. 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड (IOAA) मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया।

माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए एक वैश्विक प्रतियोगिता, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड (IOAA) का 18वां संस्करण, 11 से 21 अगस्त, 2025 तक मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। यह पहली बार था जब भारत ने इस आयोजन की मेजबानी की, जो रिकॉर्ड भागीदारी के साथ एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था।

• इस कार्यक्रम का आयोजन होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE) द्वारा किया गया था, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR), मुंबई का एक राष्ट्रीय केंद्र है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने HBCSE की विज्ञान प्रतिभा परियोजना के माध्यम से इस कार्यक्रम को व्यापक भागीदारी और सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए सहयोग प्रदान किया।

• 18वें IOAA 2025 में अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी देखी गई, जिसमें 64 देशों के 300 से अधिक छात्रों ने भाग लिया।

• भारत द्वारा पहली बार इस आयोजन की मेजबानी के साथ, प्रतिनिधित्व और उत्साह के पैमाने ने

वैश्विक वैज्ञानिक और शैक्षणिक पहलों में देश की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित किया।

Key Points:-

(i) भारत ने इस संस्करण में 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक हासिल करके उल्लेखनीय सफलता हासिल की। बेंगलुरु (कर्नाटक) के आरुष मिश्रा, दिल्ली के बनिब्रत माजी, पटना (बिहार) के पाणिनी और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के अक्षत श्रीवास्तव ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि गुरुग्राम (हरियाणा) के सुमंत गुप्ता ने रजत पदक जीता।

(ii) IOAA बोर्ड बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय यह हुआ कि भविष्य के आयोजनों के लिए इज़राइल को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय टीम के रूप में निलंबित कर दिया गया। 64 प्रतिभागी देशों के प्रतिनिधियों ने इस निर्णय के पक्ष में मतदान किया, जिससे यह अनिवार्य हो गया कि इज़राइली छात्र बिना आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के केवल व्यक्तिगत रूप से ही प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

(iii) मुंबई में IOAA 2025 के सफल आयोजन ने न केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं को उजागर किया, बल्कि शिक्षा और नवाचार में एक वैश्विक नेता के रूप में इसकी स्थिति को भी मज़बूत किया। भारतीय छात्रों की जीत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में देश की अकादमिक उत्कृष्टता को और पुष्ट किया।

IMPORTANT DAYS

1. संयुक्त राष्ट्र ने 22 अगस्त को धर्म-आधारित हिंसा के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया।

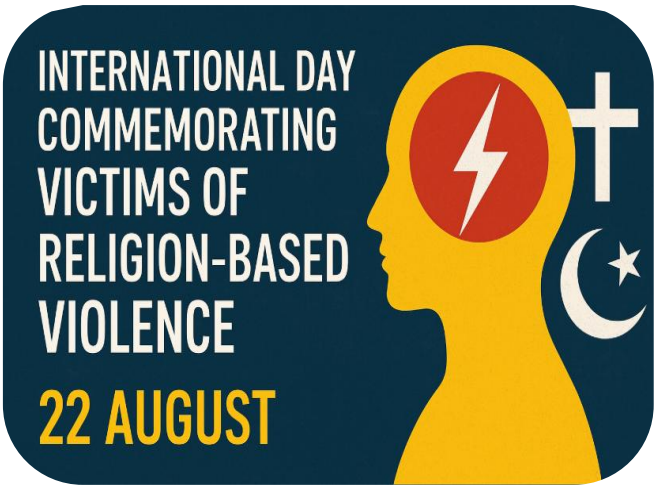

संयुक्त राष्ट्र (UN) प्रतिवर्ष 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है।

- **यह दिवस धर्म या विश्वास के आधार पर लक्षित व्यक्तियों और समुदायों के विरुद्ध हिंसा, उग्रवाद और आतंकवाद की निंदा करने की वैश्विक प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है।**

- **वर्ष 2025 में इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को 7वां वर्ष माना जाएगा, तथा 22 अगस्त को मानव अधिकारों और धर्म की स्वतंत्रता के मजबूत संरक्षण की आवश्यकता की याद दिलाई जाएगी।**

- **इस स्मरणोत्सव में दुनिया भर की सरकारों और समाजों से सभी धार्मिक समूहों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।**

Key Points:-

(i) इस आयोजन की पृष्ठभूमि संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) से जुड़ी है, जिसने 28 मई 2019 को संकल्प A/RES/73/296 को अपनाया था।

(ii) इस प्रस्ताव ने आधिकारिक तौर पर 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया।

(iii) धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 अगस्त 2019 को मनाया गया था। तब से, इसे

पीड़ितों की स्मृति का सम्मान करने और धार्मिक घृणा से प्रेरित असहिष्णुता, भेदभाव और हिंसा के कृत्यों को संबोधित करने में वैश्विक एकजुटता की पुष्टि करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है।

2. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 23 अगस्त को मनाया गया।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025, 23 अगस्त को मनाया गया, जो 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया गया। यह दिन भारत की अंतरिक्ष विजय के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है और देश भर में वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवाचार को प्रेरित करने के लिए एक उत्प्रेरक है।

• 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया, जिससे भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया।

• 2025 का विषय, "आर्यभट्ट से गगनयान: प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक", भारत की खगोलीय विरासत को - महान खगोलशास्त्री आर्यभट्ट से शुरू करते हुए - गगनयान मिशन के माध्यम से मानव अंतरिक्ष उड़ान की आकांक्षाओं से जोड़ता है।

• इस वर्ष का मुख्य कार्यक्रम भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें पैनल चर्चा, प्रदर्शनियां और "स्पेस ऑन व्हील्स" मोबाइल प्रदर्शनियां शामिल थीं, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में युवाओं के बीच अंतरिक्ष विज्ञान को लोकप्रिय बनाना था।

Key Points:-

(i) उत्तर प्रदेश में, 1.32 लाख स्कूलों के 14.8 मिलियन से अधिक छात्र NEP 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों, डिजिटल शिक्षा, प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं में शामिल हुए।

(ii) गुवाहाटी में, तारामंडलों में आयोजित कार्यक्रमों में "प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक" विषय पर प्रदर्शनियाँ प्रदर्शित की गईं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और ISRO के वैज्ञानिक जनहित में कार्यक्रम में उपस्थित थे।

(iii) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमी-क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की और अंतरिक्ष में मानवता की गहरी पैठ पर विश्वास व्यक्त किया। इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) के मॉडल का अनावरण किया और रक्षा मंत्री जितेंद्र सिंह ने रणनीतिक क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रकाश डाला और राष्ट्रीय सुरक्षा में इसके अनुप्रयोगों को रेखांकित किया।

OBITUARY

1. श्रीनिवासन के. स्वामी को 2025-26 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ (AAAI) का पुनः अध्यक्ष चुना गया।

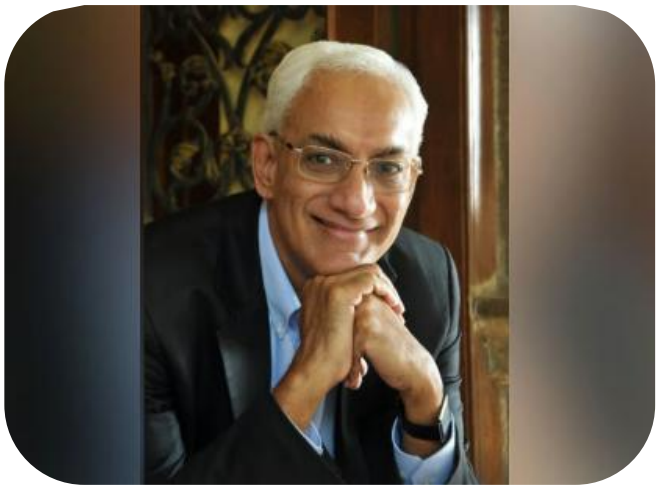

14 अगस्त 2025 को, आर के स्वामी लिमिटेड के कार्यकारी समूह अध्यक्ष, श्रीनिवासन के स्वामी को वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ (AAAI) के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया - इस पद पर उनका यह चौथा कार्यकाल होगा, जबकि जयदीप गांधी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

• श्रीनिवासन स्वामी का हालिया चुनाव 18 साल के अंतराल के बाद AAAI के शीर्ष पर उनकी वापसी का प्रतीक है। इससे पहले उन्होंने 2004 से 2007 तक लगातार तीन कार्यकालों तक इस पद पर कार्य किया था, जिसने उन्हें उद्योग जगत के एक अनुभवी और विश्वसनीय दिग्गज के रूप में स्थापित किया।

• यह नियुक्ति 14 अगस्त 2025 को आयोजित AAAI की वार्षिक आम सभा में हुई। स्वामी के साथ, जयदीप गांधी को उपाध्यक्ष चुना गया। नए बोर्ड में लियो बर्नेट, मैडिसन कम्युनिकेशंस, ग्रे वर्ल्डवाइड, हवास मीडिया जैसी प्रमुख एजेंसियों के प्रमुख लोग शामिल हैं।

• भारत के विज्ञापन और विपणन संचार क्षेत्र के दिग्गज स्वामी ने पहले कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में नेतृत्व की भूमिका निभाई है - जिनमें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ (IAA), एशियाई विज्ञापन एजेंसी संघ का परिसंघ, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद और ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन शामिल हैं - जो उनके व्यापक प्रभाव और प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

Key Points:-

(i) निवर्तमान अध्यक्ष प्रशांत कुमार, जिन्होंने 2022-23 से 2024-25 तक सेवा की, ने स्वामी की वापसी का स्वागत किया और विश्वास व्यक्त किया कि स्वामी की व्यापक विशेषज्ञता AAAI को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी। कुमार अब AAAI बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

(ii) AAAI के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से व्यापक रूप से सम्मानित स्वामी ने उद्योग मानकों को आगे बढ़ाने, सहयोग को बढ़ावा देने और भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन हितों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में उनकी विरासत मजबूत हुई है।

Static GK

Kerala	मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन	राज्यपाल: राजेंद्र आर्लेकर
United States	राजधानी: वाशिंगटन, डी.सी.	राष्ट्रपति: डोनाल्ड ट्रम्प
United Nations (UN)	महासचिव (SG) : एंटोनियो गुटेरेस	मुख्यालय : न्यूयॉर्क
Odisha	मुख्यमंत्री: मोहन चरण माझी	राज्यपाल: हरि बाबू कंभमपति
Assam	मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा	राज्यपाल: लक्ष्मण आचार्य
Power Finance Corporation Limited (PFC)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) : परमिंदर चोपड़ा	मुख्यालय: नई दिल्ली
Ministry of Tribal Affairs (MoTA)	मंत्री: दुर्गा दास उइके	मुख्यालय: नई दिल्ली
L&T Finance	CEO : सुदीप्त रॉय	मुख्यालय: मुंबई
Japan International Cooperation Agency (JICA)	राष्ट्रपति: शिनिची किताओका	मुख्यालय: टोक्यो, जापान
Russia	राजधानी: मास्को	प्रधान मंत्री: मिखाइल मिशुस्टिन
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई